करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

अक्तूबर 2021 (संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **5**

- मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (MRHRU) 5
- राज्य लघु वनोपज संघ का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ अनुबंध 5
- राम वन गमन पर्यटन परिपथ का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ 6
- छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिज़र्व 6
- प्रधानमंत्री ने अंबेडकर अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया 7
- ग्रामीण औद्योगिक पार्क में उपयोग किये जाएंगे आईजीएयू के नवाचार 7
- प्रदेश में मनाया गया 'मद्यपान निषेध सप्ताह' 8
- सांसद आदर्श ग्राम योजना में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर 8
- मिशन मोड पर गोठानों से बिजली उत्पादन 9
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी 10
- माई स्टेम्प योजना 10
- छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का किया लोकार्पण 10
- छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड 11
- कलागुड़ी 11
- मुरिया दरबार 12

नोट :

- बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लेंग्वेज (बादल) 13
- आईएएनएस-सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स 13
- सहभागी लोकतंत्र एवं विकेंद्रीकृत योजना निर्माण संबंधी टास्क फोर्स 14
- बस्तर दशहरा 15
- श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ 15
- 'इंडिया ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड' 16
- 'हैंडबुक ऑफ ओस्टियोपोरोसिस ए प्रीवेंटेबल डिजीज' 16
- 'ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप' 16
- 'वर्टेब्रोप्लास्टी' सर्जरी 17
- 'भूलन द मेज' को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार 17
- छत्तीसगढ़ शौर्य पदक 18
- राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव, 2021 19
- 11वाँ मेडिकल कॉलेज 19
- सिल्क मार्क 20

The Vision

नोट :

दृष्टि
The Vision

नोट :

छत्तीसगढ़

मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (MRHRU)

चर्चा में क्यों ?

- 30 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम (सीजीएमएससी) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले के झीट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (MRHRU) की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य शासन की ओर से सीजीएमएससी के प्रबंध निदेशक कार्तिकेय गोयल और आईसीएमआर की ओर से राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (NTHRI), जबलपुर के निदेशक डॉ. अरूप दास ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- इसके तहत एमआरएचआरयू चिकित्सा कर्मचारियों को बीमारियों के निदान, निगरानी, अनुसंधान और प्रशिक्षण में मदद करेगी।
- यह मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई 2 करोड़ रुपए के निवेश से 11,000 वर्ग फुट में स्थापित की जाएगी।
- इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अब तक वेक्टर जनित बीमारियों के नमूने जाँच के लिये जबलपुर और अन्य राज्यों में भेजे जाते थे। अब प्रदेश में ही यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

राज्य लघु वनोपज संघ का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ अनुबंध

चर्चा में क्यों ?

- 5 अक्टूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से अनुबंध किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को संग्रहण, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु नवीनतम उपकरण एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे।
- समझौते के तहत उपलब्ध आधुनिकतम उपकरणों तथा तकनीकी का प्रयोग लघु वनोपज संग्रहण में लगे लोगों की मेहनत कम करेगा तथा उन्नत संग्रहण सुनिश्चित होगा। साथ ही नई तकनीक के प्रयोग से वनोपजों की साफ-सफाई, छटाई, गोदामीकरण में सुधार एवं सरलता के साथ 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' में नए उत्पादों का समावेश होगा और वन-धन केंद्रों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी।
- इसके अलावा आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों से उपलब्ध तकनीकी के प्रयोग से संग्राहकों तथा स्व-सहायता समूहों को अधिक आमदनी, बढ़ा हुआ लाभांश तथा छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित समाज कल्याण की योजनाओं, जैसे- सामाजिक सुरक्षा, बीमा, छात्रवृत्ति आदि का अधिक-से-अधिक लाभ मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कोदो-कुटकी एवं रागी के बेहतर प्रसंस्करण कार्य के लिये भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) के साथ समझौता किया जा चुका है।
- यह अनुबंध राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्राहक आदिवासी तथा अन्य परंपरागत वनवासी परिवारों की बेहतरी की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि आईसीएआर भारत सरकार के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत् एक स्वशासी संस्था है। यह देश में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्यपालन तथा पशुविज्ञान में समन्वय स्थापित करने एवं मार्गदर्शन देने वाली सर्वोच्च संस्था है।

राम वन गमन पर्यटन परिपथ का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 7 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भगवान श्रीराम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये प्रारंभ की गई राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के प्रथम चरण का माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण तथा भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊँची प्रतिमा का लाईट के माध्यम से अनावरण किया।
- गौरतलब है कि कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार एवं परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य 15 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ के बारे में कहा कि कोरिया ज़िले के सीतामढ़ी में हरचौका से लेकर सुकमा के रामाराम तक लगभग 2260 किलोमीटर का राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम के ननिहाल के रूप में संपूर्ण विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। इस पर्यटन परिपथ में कोरिया ज़िले से सुकमा तक कदम-कदम पर भगवान श्रीराम के दर्शन होंगे और उनसे जुड़ी महत्त्व की कथाएँ देखने और सुनने को मिलेंगी।
- राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना में सीतामढ़ी हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (सरगुजा), शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाज़ार), चंदखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), सिहावा सप्तऋषि आश्रम (धमतरी), जगदलपुर (बस्तर) और रामाराम (सुकमा) का 133 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से पर्यटन की दृष्टि से विकास का कार्य किया जा रहा है।
- इस पर्यटन परिपथ के माध्यम से राज्य में न केवल ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन के नए वैश्विक अवसर बढ़ेंगे।
- माता कौशल्या मंदिर परिसर में भव्य गेट, मंदिर के चारों ओर तालाब का सौंदर्यीकरण, आकर्षक पथ निर्माण, वृक्षारोपण किया गया है। मंदिर चारों ओर से मनमोहक उद्यानों से घिरा है, तालाब के मध्य में शेषनाग शैबया पर शयन मुद्रा में भगवान विष्णु के चरण दबाती माँ लक्ष्मी की आकर्षक प्रतिमा है, दूसरी ओर समुद्र मंथन के दृश्य को प्रतिबिंबित करती हुई देव-दानवों की मूर्तियाँ श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।

छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' (एनटीसीए) ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिज़र्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित यह नया टाइगर रिज़र्व उदंती-सीतानदी, अचानकमार और इंद्रावती टाइगर रिज़र्व के बाद छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिज़र्व होगा।
- इस प्रस्ताव पर एनटीसीए की 11वीं तकनीकी समिति ने 1 सितंबर को विचार किया और एक महीने बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ट(1) के तहत मंज़ूरी दी गई।

नोट :

- तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की पहचान 2011 में सरगुजा जशपुर हाथी रिज़र्व के हिस्से के रूप में की गई थी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अविभाजित मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था। दोनों 2011 से टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित होने के लिये कतार में थे।
- नए टाइगर रिज़र्व की घटक इकाइयाँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य क्रमश: 1,44,000 हेक्टेयर (1,440 वर्ग किमी.) और 60,850 हेक्टेयर (608.5 वर्ग किमी.) में फैली हुई हैं।
- गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया ज़िले में है, जबकि तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के उत्तर-पश्चिमी कोने में सूरजपुर ज़िले में है।
- गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात निवास स्थान था। मूल रूप से संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 2001 में राज्य के गठन के बाद छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में एक अलग इकाई के रूप में बनाया गया था।
- राज्य में वन्यजीव विशेषज्ञों और कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिज़र्व में बदलना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है और बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिज़र्व के बीच बाघों के आने-जाने के लिये एक गलियारा प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने अंबेडकर अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

- 7 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में पीएम केयर फंड के तहत स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक प्रेशर स्विंग एड्सोर्पसन (पीएसए) ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया।
- यह प्लांट एक मिनट में 960 लीटर ऑक्सीजन पैदा कर सकता है।
- मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित 1,450 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट है।
- दोनों संयंत्रों के कामकाज के साथ, अस्पताल में 500 ऑक्सीजन सिलेंडरों की ऑक्सीजन की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक परिचालन सुविधा होगी।

ग्रामीण औद्योगिक पार्क में उपयोग किये जाएंगे आईजीएयू के नवाचार

चर्चा में क्यों ?

- 8 अक्टूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि उत्पादों को संसाधित करने के प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीएयू) के नवाचारों का उपयोग गाँवों में स्थापित किये जा रहे ग्रामीण औद्योगिक पार्क में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीकेयू के नवाचार कृषि और लघु वनोपज उत्पादों के प्रसंस्करण में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के दृष्टिकोण के अनुसार गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है।
- इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने आईजीएयू परिसर में एक कृषि विज्ञान केंद्र भवन, एक अक्की जैवविविधता संग्रहालय और एक ज्ञान केंद्र भवन का भी उद्घाटन किया।

नोट :

- इसके साथ ही उन्होंने धान (paddy), सोयाबीन (soyabean), मक्का (maize) और रास्पबेरी (raspberry) सहित आठ फसलों की उन्नत किस्मों के बीज लॉन्च किये और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित चावल से प्रोटीन और ग्लूकोज को अलग करने की तकनीक का उद्घाटन भी किया।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण के मामले में विगत दो वर्षों से देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। 'द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राईफेड)' द्वारा जारी किये गए आँकड़ों के अनुसार राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रथम तिमाही, माह अप्रैल से जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि के 2 लाख 77 हज़ार 958 क्विंटल लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, जो देश में इस दौरान 93 करोड़ रुपए मूल्य के कुल संगृहीत लघु वनोपजों का 88.36 प्रतिशत है।

प्रदेश में मनाया गया 'मद्यपान निषेध सप्ताह'

चर्चा में क्यों ?

- 2 से 8 अक्टूबर, 2021 तक प्रदेश में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा 'मद्यपान निषेद्य सप्ताह' का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशापान के बुरे प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

प्रमुख बिंदु

- समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने भारत माता वाहिनी योजना के तहत बालोद ज़िले में नशामुक्ति रथ को रवाना करते हुए, इसका शुभारंभ किया था। इसके साथ ही विभिन्न ज़िलों में कलेक्टरों द्वारा जागरूकता रथ को रवाना किया गया।
- स्कूल और कॉलेजों में नशा उन्मूलन विषय पर सेमीनार और निबंध लेखन, रंगोली-चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
- इसके साथ ही संगोष्ठियों और जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को समझाया गया कि नशा व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान पहुँचाता है।
- योग आयोग के माध्यम से योग शिविर आयोजित कर नशापान से होने वाली बीमारियों के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई और समझाया गया कि योग के माध्यम से जीवन को संयमित और स्वस्थ बनाया जा सकता है।
- शराब व्यसन मुक्ति अभियान के तहत ये रथ गाँव-गाँव घूमकर नशामुक्ति हेतु जनजागरूकता लाने का काम करेंगे। इस अवसर पर भारत माता वाहिनी दल की महिलाओं द्वारा भी जागरूकता रैली निकाली गई।

सांसद आदर्श ग्राम योजना में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक इस योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर, जबकि तमिलनाडु पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों के मुताबिक 9 अक्टूबर, 2021 तक योजना के तहत 2314 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है और ग्राम विकास की योजनाबद्ध 82,918 परियोजनाओं में से 53,352 परियोजनाएँ एवं गतिविधियाँ पूरी हुई हैं, जबकि 6,416 ग्राम विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
- वहीं योजना के तहत ग्राम विकास की 23,110 परियोजनाओं एवं गतिविधियों पर काम शुरू नहीं हुआ है, जो कुल कार्यों का एक-चौथाई से कुछ अधिक (28 प्रतिशत) है। योजना के लिये चयनित 2,314 ग्राम पंचायतों में से 1,717 ग्राम पंचायतों ने पोर्टल पर ग्राम विकास परियोजना का ब्योरा अपलोड किया है।

नोट :

- आँकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु (94.3 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (89.8 प्रतिशत), गुजरात (84.2 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (79.67 प्रतिशत), कर्नाटक (76.68 प्रतिशत), उत्तराखंड (76.66 प्रतिशत), केरल (69.78 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (68.4 प्रतिशत), मणिपुर (67.57 प्रतिशत), मिज़ोरम (66.32 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (65.25 प्रतिशत) और हरियाणा (61.16 प्रतिशत) में आदर्श ग्राम योजना के कार्यों का क्रियान्वयन अच्छा है।
- वहीं इस योजना के तहत राजस्थान में 55.06 प्रतिशत, झारखंड में 52.63 प्रतिशत, तेलंगाना में 50.38 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 45.46 प्रतिशत, ओडिशा में 43.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 42.11 प्रतिशत, बिहार में 38.68 प्रतिशत, पंजाब में 36.97 प्रतिशत ग्राम विकास का कार्य पूरा हुआ है।
- गौरतलब है कि गाँवों के विकास के लिये सांसद आदर्श ग्राम योजना का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में किया था। 11 अक्टूबर, 2014 को यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत सांसदों को अपने क्षेत्र में एक 'आदर्श ग्राम' का चयन करके उसका विकास करना था।
- योजना के तहत 2014 से 2019 के बीच चरणबद्ध तरीके से सांसदों को तीन गाँव और 2019 से 2024 के बीच पाँच गाँव गोद लेने थे।
- योजना के तहत मुख्यरूप से चार वर्गों- वैयक्तिक विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देकर ग्राम विकास करने की बात कही गई है। इसके तहत स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, बुनियादी सुविधाएँ, सामाजिक न्याय व सुशासन आदि कार्यों को शामिल किया गया है।
- 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के लिये अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है और सांसदों को सांसद निधि (एमपीलैड) के कोष से ही इसका विकास करना होता है।

मिशन मोड पर गोठानों से बिजली उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

- 11 अक्टूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'गोधन न्याय योजना' के तहत पशुपालकों, गोबर संग्राहकों को गोबर खरीदी, लाभांश के रूप में महिला स्वयं सहायता समूहों तथा गोठान समितियों के खाते में कुल 7.36 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करते हुए कहा कि गाय के गोबर से बिजली का उत्पादन 'मिशन मोड' पर किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 16 सितंबर से 30 सितंबर तक खरीदे गए गोबर के बदले पशुपालकों और गोबर संग्राहकों के खाते में 1.87 करोड़ रुपए, लाभांश की राशि के रूप में महिला स्व-सहायता समूह को 2.14 करोड़ रुपए तथा गोठान समितियों को 3.25 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठानों से उत्पन्न बिजली राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाएगी, जिससे गाँवों को राजस्व प्राप्त होगा। रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग ज़िले में पहले से ही तीन गोठान बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। जल्द ही गाँवों को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के मिशन मोड में संचालन के लिये गोधन न्याय मिशन का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत गोठानों में जरूरी अधोसंरचनाओं का निर्माण तेजी से किया जाएगा। किसानों, पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों और गोठान समितियों के आय में वृद्धि करने के उपाय किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 10,501 गोठानों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7460 गोठान निर्मित हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना में अब तक 52 लाख 21 हज़ार क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'महिला स्वयं सहायता समूहों' को गाय के गोबर को वर्मी कम्पोस्ट में परिवर्तित करने का सीमित कार्य ही नहीं दिया जाएगा बल्कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की मदद से विभिन्न रोज़गारमूलक गतिविधियाँ प्रारंभ की जाएंगी।
- गोठानों में जैविक खाद बनाने, सामुदायिक किचन गार्डन के अलावा मशरूम उत्पादन, मत्स्यपालन, बकरीपालन, मुर्गीपालन और गाय के गोबर से विभिन्न उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- इस अवसर पर कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि गोठानों को बहुस्तरीय आर्थिक गतिविधियों के लिये ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में बदला जा रहा है।

नोट :

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी

चर्चा में क्यों ?

- 12 अक्टूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थानांतरण से पूर्व आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे।
- न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा का स्थान लिया, जिनका स्थानांतरण आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किया गया है।
- हालाँकि वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण कोलेजियम व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, जिसका वर्तमान स्वरूप 'थर्ड जजेस केस 1998' में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से विकसित हुआ है।

माई स्टेम्प योजना

चर्चा में क्यों ?

- 14 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में भारतीय डाक विभाग, छत्तीसगढ़ परिमंडल द्वारा 'माई स्टेम्प योजना' के तहत राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव पर डाक टिकट एवं विशेष आवरण का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह डाक टिकट देश के सभी बड़े डाकघरों के काउंटरों में उपलब्ध होगा तथा टिकट का संग्रहण करने वालों के लिये उपयोगी होगा।
- इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल आर.के. जायभाय ने बताया कि विशेष आवरण छत्तीसगढ़ राज्य के 21वें स्थापना दिवस एवं इस दौरान 28, 29 और 30 अक्तूबर 2021 को राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहे द्वितीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उपलक्ष्य में जारी किया गया है।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आमंत्रण सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल/प्रशासक और जनजातीय कलाकारों को भेजा गया है।
- इस नृत्य महोत्सव में भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जनजातीय कलाकारों द्वारा कला और संस्कृति की अपनी समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 14 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया। शासकीय आयोजनों में यह गमछा अतिथियों को भेंट किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ द्वारा ये गमछे टसर सिल्क एवं कॉटन बुनकरों तथा गोदना हस्त शिल्पियों द्वारा तैयार किये गए हैं।
- गमछे पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी- पहाड़ी मैना, राजकीय पशु-वन भैंसा, मांदर, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट और लोक नृत्य करते लोक कलाकारों के चित्र गोदना चित्रकारी से अंकित किये गए हैं।

नोट :

- गमछे की डिज़ाइन में धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिये धान की बाली तथा हल जोतते किसान को दर्शाया गया है। सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्र कला की छाप गमछे के बार्डर में अंकित की गई है।
- गमछा तैयार करने के पारिश्रमिक के अलावा गमछे से होने वाली आय का 95 प्रतिशत हिस्सा बुनकरों तथा गोदना शिल्पकारों को दिया जाएगा।
- टसर सिल्क गमछे में बुनकर द्वारा ताने में फिलेचर सिल्क यार्न तथा बाने में डाभा टसर यार्न एवं घींचा यार्न का उपयोग किया गया है। गमछे की चौड़ाई 24 इंच तथा लंबाई 84 इंच है।
- इस टसर सिल्क गमछे की बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा की गई है। गमछे की बुनाई के उपरांत उनमें सरगुजा की महिला गोदना शिल्पियों के द्वारा गोदना प्रिंट के माध्यम से डिज़ाइनों को उकेरा गया है।
- कॉटन गमछे को राज्य के बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव के बुनकरों द्वारा हथकरघों पर बुनाई के माध्यम से तैयार किया गया है।
- गमछे में ताने में 2/40 काउंट का कॉटन यार्न तथा बाने में 20 माउंट का कॉटन यार्न उपयोग किया गया है। इसकी भी चौड़ाई 24 इंच तथा लंबाई 84 इंच है।
- एक सिल्क गमछे का मूल्य 1,534 रुपए (जी.एस.टी. सहित) निर्धारित है। सिल्क गमछे की बुनाई मज़दूरी 120 रुपए प्रति नग है, जबकि कॉटन गमछे का मूल्य 239 रुपए (जी.एस.टी. सहित) प्रति नग निर्धारित है।
- इन गमछों को राज्य के स्मृति चिह्न के रूप में मान्यता दिये जाने से बुनाई के माध्यम से 300 बुनकरों को तथा 100 गोदना शिल्पियों को वर्ष भर का रोज़गार प्राप्त होगा। कॉटन गमछे की बुनाई मज़दूरी 60 रुपए प्रति नग है।

छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड

- 17 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के स्थानीय कृषकों एवं प्रसंस्करणकर्त्ताओं को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने और राज्य में चाय-कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिये कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन किये जाने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस बोर्ड में उद्योग मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में मुख्यमंत्री सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक, कृषि उद्यानिकी तथा वन विभाग के एक-एक अधिकारी सहित दो विशेष सदस्य भी शामिल किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 3 वर्षों में कम-से-कम दस-दस हज़ार एकड़ में चाय एवं कॉफी की खेती करने का लक्ष्य अर्जित किया जाएगा। चाय एवं कॉफी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं कृषि विभाग की अन्य सुविधाएँ दी जाएँगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के उत्तरी भाग, विशेषकर जशपुर ज़िले में चाय तथा दक्षिणी भाग, विशेषकर बस्तर ज़िले में कॉफी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाएँ हैं।
- इसमें उद्यानिकी एवं उद्योग विभाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी मार्ग-दर्शन लेने के साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, निवेशकों एवं कंसल्टेंट्स की सहायता भी ली जाएगी।

कलागुड़ी

चर्चा में क्यों ?

- 17 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर ज़िले के मुख्यालय जगदलपुर में दलपत सागर के निकट बनाए गए कलागुड़ी (बस्तर आर्ट गैलरी) का लोकार्पण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बस्तर शिल्पकलाओं के विक्रय हेतु बस्तर ज़िला प्रशासन और फ्लिपकार्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर की हस्तशिल्प कलाओं के जीवंत प्रदर्शन के लिये निर्मित इस परिसर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान यह भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में पहुँच चुका था। वर्तमान में इसका उपयोग लोक निर्माण विभाग द्वारा अभियांत्रिकी कार्यशाला के रूप में किया जा रहा था।
- बस्तर की पारंपरिक हस्तशिल्प कलाओं से सैलानियों के साथ युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिये इस परिसर में स्थित जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण किया गया है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यहाँ बनाए गए आर्ट गैलरी का भ्रमण कर लोक कलाकारों द्वारा निर्मित लौह शिल्पकारी, मृदा शिल्पकारी, बेलमेटल की शिल्पकारी और सीसल शिल्पकारी का जीवंत प्रदर्शन देखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ कैफेटेरिया में बस्तर कॉफी का स्वाद भी लिया।
- इस आर्ट गैलरी में यहाँ 30 वर्षों से सूखी लकड़ियों के माध्यम से कला का प्रदर्शन कर रहे डाइट के सहायक प्राध्यापक सुभाष श्रीवास्तव के ड्रिफआर्ट और कोलाज पर कागज से निर्मित कलाकृतियों के साथ ही बेलमेटल से निर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया था। इसके साथ ही यहाँ एक अन्य कक्ष में लक्ष्मी जगार और धनकुल जगार के अवसर पर भित्तियों में बनाई जाने वाली जगार चित्र की कार्यशाला भी लगाई गई थी।

मुरिया दरबार

चर्चा में क्यों ?

- 17 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के तहत सिरहासार में आयोजित 'मुरिया दरबार' में शामिल हुए तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई माँगों को पूरा करते हुए विभिन्न घोषणाएँ कीं।

प्रमुख बिंदु

- मुरिया दरबार में शामिल होने के लिये सिरहासार पहुँचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत मांझी-चालकियों द्वारा पारंपरिक पगड़ी पहनाकर किया गया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टेंपल कमेटी के लिये एक लिपिक और एक भृत्य की भर्ती की घोषणा करने के साथ ही यहाँ स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नामकरण वीर झाड़ा सिरहा के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर में आधुनिक ज्योति कक्ष के निर्माण की घोषणा भी की।
- बस्तर में मुरिया दरबार की शुरुआत 8 मार्च, 1876 को हुई थी, जिसमें सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर मेक जार्ज ने मांझी- चालकियों को संबोधित किया था। बाद में लोगों की सुविधा के अनुरूप इसे बस्तर दशहरा का अभिन्न अंग बनाया गया, जो परंपरानुसार 145 साल से जारी है।
- उल्लेखनीय है कि बस्तर रियासत द्वारा अपने राज्य में परगना स्थापित कर यहाँ के मूल आदिवासियों से मांझी (मुखिया) नियुक्त किया गया था, जो अपने क्षेत्र की हर बात राजा तक पहुँचाया करते थे, वहीं राजाज्ञा से ग्रामीणों को अवगत भी कराते थे। मूरिया दरबार में राजा द्वारा निर्धारित 80 परगना के मांझी ही उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हैं।
- मुरिया दरबार में पहले राजा और रियासत के अधिकारी कर्मचारी मांझियों की बातें सुना करते थे और तत्कालीन प्रशासन से उन्हें हल कराने की पहल होती थी। आज़ादी के बाद मुरिया दरबार का स्वरूप बदल गया। 1947 के बाद राजा के साथ जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने लगे।
- 1965 के पूर्व बस्तर महाराजा स्व. प्रवीर चंद्र भंजदेव दरबार की अध्यक्षता करते रहे। उनके निधन के बाद राज परिवार के सदस्यों मुरिया दरबार में आना बंद कर दिया था। वर्ष 2015 से राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव इस दरबार में शामिल हो रहे हैं।
- बस्तर के मुरिया दरबार में अब बस्तर संभाग के निर्वाचित जन-प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते हैं। वे ग्रामीणों से आवेदन लेते हैं। मांझी, चालकी और मेंबर-मेंबरीन इनके सामने ही अपनी समस्या रखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी 2009 -10 से लगभग हर मुरिया दरबार में शामिल हो रहे हैं।

नोट :

बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लेंग्वेज (बादल)

चर्चा में क्यों ?

- 17 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के समीप आसना ग्राम में बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोलियाँ, साहित्य एवं शिल्पकला के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लेंग्वेज (बादल) का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर बादल एकेडमी और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय द्वारा बादल एकेडमी में लोक नृत्य और लोक संगीत के लिये साझा तौर पर कार्य किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा बादल एकेडमी को मान्यता प्रदान करते हुए अपने पाठ्यक्रमों से संबंधित विधाओं का संचालन किया जाएगा।
- बादल अकादमी में लाइब्रेरी, रिकॉर्ड्रिंग रूम, ओपन थिएटर, डांस गैलरी, चेंजिंग रूम, गार्डन एवं रेसिडेंशियल हाउस, पाथवे, एग्जीबिशन हॉल, कैफेटेरिया बनाए गए हैं।
- बादल एकेडमी के जरिये बस्तर की विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण करना, बाकी देश-दुनिया से इनका परिचय कराना, शासकीय कार्यों का सुचारू संपादन के लिये यहाँ के मैदानी कर्मचारी-अधिकारियों को स्थानीय बोली-भाषा का प्रशिक्षण देना आदि कार्य किया जाएगा।
- इस अकादमी में प्रमुख रूप से लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रभाग, लोक साहित्य प्रभाग, भाषा प्रभाग और बस्तर शिल्प कला प्रभाग की स्थापना की गई है।
- लोक गीत एवं लोक नृत्य प्रभाग के तहत बस्तर के सभी लोक गीत, लोक नृत्य गीत का संकलन, ध्वन्यांकन, फिल्मांकन एवं प्रदर्शन का नई पीढ़ी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें गंवर सिंग नाचा, डंडारी नाचा, धुरवा नाचा, परब नाचा, लेजागीत, मारीरसोना, जगार गीत आदि प्रमुख हैं।
- लोक साहित्य प्रभाग के तहत बस्तर के सभी समाजों के धार्मिक रीति-रिवाज, सामाजिक ताना-बाना, त्योहार, कविता, मुहावरा आदि का संकलन लिपिबद्ध कर जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा।
- भाषा प्रभाग के तहत बस्तर की प्रसिद्ध बोली हल्बी, गोंडी, धुरवी और भतरी बोली का स्पीकिंग कोर्स तैयार कर लोगों को इन बोलियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इसी तरह बस्तर शिल्प कला प्रभाग के तहत बस्तर की शिल्प कलाओं में काष्ठकला, धातु कला, बाँसकला, जूटकला, तुंबा कला आदि का प्रदर्शन एवं निर्माण करने की कला सिखाई जाएगी।
- बादल एकेडमी में निर्मित तीन भवनों का नामकरण वीर शहीदों के नाम पर किया गया है। इनमें प्रशासनिक भवन का नाम शहीद झाड़ा सिरहा के नाम पर, आवासीय परिसर का नाम हल्बा जनजाति के शहीद गेंदसिंह के नाम पर और लायब्रेरी व अध्ययन भवन को धुरवा समाज के शहीद वीर गुंडाधुर के नाम पर किया गया है।
- इसके साथ ही यहाँ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में थिंक-बी और आईआईएम रायपुर, आईआईआईटी रायपुर, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंसेज के साथ एमओयू किया गया। उद्यमिता और स्वरोज़गार के इच्छुक बस्तर के युवाओं के स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के साथ ही उन्हें इंक्यूबेट करने के लिये यह एमओयू किया गया।

आईएएनएस-सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स

चर्चा में क्यों ?

- 18 अक्तूबर, 2021 को जारी आईएएनएस-सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बघेल को सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- आईएएनएस ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के कारण यह लोकप्रियता मिली है।
- आईएएनएस के अनुसार भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है, जिन्होंने कोविड-19 के लिये माता-पिता/अभिभावकों को खो दिया है। 'महतारी दुलार योजना' के तहत ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार वहन कर रही है।
- नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट-2020-21 के अनुसार, सतत् विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। नीति आयोग 115 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है।
- पिछले साल, छत्तीसगढ़ ने लैंगिक समानता पैरामीटर पर 43 अंक हासिल किये और भारत में सातवें स्थान पर था। इस साल, छत्तीसगढ़ ने 61 स्कोर किया और चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा।
- सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने कहा, 'ऐसे मुख्यमंत्रियों को लोगों ने पसंद किया है, जिनमें निर्णय लेने की क्षमताएँ हैं और जिनके काम करने की शैली सीईओ जैसी है।'

सहभागी लोकतंत्र एवं विकेंद्रीकृत योजना निर्माण संबंधी टास्क फोर्स

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य योजना आयोग द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग की मंशा के अनुरूप सहभागी लोकतंत्र व विकेंद्रीकृत योजना निर्माण के संबंध में राज्य शासन को सुझाव देने हेतु टास्कफोर्स का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस टास्कफोर्स के अध्यक्ष अमरजीत भगत, मंत्री खाद योजना आर्थिक एवं साख्यिकी होंगे।
- टास्कफोर्स के सदस्यों में पाँच माननीय सांसद, पाँच विधायक, पाँच ज़िला पंचायत के अध्यक्षों तथा दो-दो नगर-निगमों, नगर-पालिकाओं व नगर-पंचायतों के अध्यक्षों एवं प्रदेश में मान्यता प्राप्त दलों के प्रदेश अध्यक्षों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र से जुड़े विषय-विशेषज्ञों को भी टास्कफोर्स में शामिल किया गया है।
- टास्कफोर्स का संयोजन सचिव विभागाध्यक्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग करेंगे।
- यह टास्कफोर्स योजना निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर सुझाव देगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक अंकेक्षण के लिये नागरिकों के सशक्तीकरण, वित्तीय प्रबंधन व निगरानी के लिये नागरिकों को प्रशिक्षित करने का उपाय सुझाएगा।
- राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य शासन को सुझाव देने के लिये समय-समय पर विशेषज्ञ टास्क फोर्सेस का गठन किया जाता है, जिसमें देश के एवं स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ एवं ज़मीनी कार्यकर्त्ताओं को शामिल किया जाता है।
- टास्कफोर्स द्वारा विचार-विमर्श उपरांत राज्य शासन को उचित नीतियाँ सुझायी जाती हैं।
- योजना आयोग द्वारा मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत राज्य के विकास के प्रासंगिक विषयों पर सुझाव देने विभिन्न टास्कफोर्सेस का गठन किया गया है।
- टास्कफोर्स के विषयों में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि, जल संवर्द्धन, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्र, आदिवासी विकास, वन एवं वन्य जीव प्रबंधन, लघु वनोपज प्रबंधन, स्वास्थ्य, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा, उद्योग, ग्रामोद्योग कौशल विकास, उच्च व तकनीकी शिक्षा तथा रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, श्रमिक कल्याण, कला, पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति संवर्द्धन जैसे महत्त्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
- यह टास्कफोर्सेस प्रदेश में विद्यमान समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पाई गई नीतियों, कार्यक्रमों एवं श्रेष्ठ प्रयासों को प्रदेश में लागू करने की व्यवहारिकता और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार एवं सुझाव रखे जाते हैं।

नोट :

बस्तर दशहरा

चर्चा में क्यों ?

- 19 अक्तूबर, 2021 को सबसे लंबे समय तक चलने वाले (75 दिवसीय) विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का समापन माता मावली की भावभीनी विदाई के साथ हो गया। परंपरा अनुसार बस्तर संभाग के 84 परगना और सीमावर्ती राज्यों से आए 450 से अधिक देवी-देवताओं को कुटुंब जात्रा के बाद ससम्मान विदाई दी गई।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष बस्तर दशहरे की शुरुआत पाट जात्रा विधान के साथ 8 अगस्त, 2021 को हुई थी।
- माँ मावली की डोली व माँ दंतेश्वरी के छत्र की पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। वहीं बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव ने परंपरा के अनुसार माता की डोली को स्वयं कंधे पर उठाया और नगर परिक्रमा करवाई।
- दंतेश्वरी मंदिर से प्रगति पथ तक जगह-जगह विशाल जनसमुदाय ने माता मावली को भावभीनी विदाई दी। विदाई रस्म के दौरान पुलिस जवानों ने हर्ष फायरिंग भी की।
- उल्लेखनीय है कि बस्तर दशहरा शेष भारत के दशहरे से भिन्न है, क्योंकि शेष भारत में दशहरा रावण के वध के प्रति, जबकि बस्तर दशहरा दंतेश्वरी माता के प्रति समर्पित है। यह पर्व श्रावण अमावस्या से लेकर अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है।
- बस्तर की यह रियासतकालीन परंपरा 620 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इसका प्रारंभ काकतीयवंशीय शासक पुरुषोत्तमदेव (1408 से 1439 ई.) ने किया था।

श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 20 अक्तूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत उन्होंने राज्य में 84 दुकानों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत दुर्ग ज़िले और जांजगीर-चांपा ज़िले में 15-15, धमतरी, कोरबा और रायगढ़ में 6-6, राजनांदगांव में 5, बिलासपुर, कोंडागांव, सुकमा और बीजापुर में 3-3, रायपुर, गोरेला-पेंड्रा-मरवाही, सूरजपुर और जशपुर में 2-2 मेडिकल स्टोर खोले गए हैं।
- महासमुंद, बलौदाबाज़ार-भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम, सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा ज़िलों में एक-एक स्टोर खोले गए हैं।
- श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध होगी। उपभोक्ताओं को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50.09 प्रतिशत और अधिकतम 71 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दवाइयों की होम किट और ट्रैवल किट का लोकार्पण भी किया। यह किट श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर में विक्रय के लिये उपलब्ध होगी। होम किट की कीमत 691 रुपए है, जो इन मेडिकल स्टोर में 290 रुपए के मूल्य पर तथा ट्रेवल किट, जिसकी कीमत 311 रुपए है, वह 130 रुपए में उपलब्ध होगी।
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना में आने वाले समय में प्रदेश के 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयाँ तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। इसके अलावा वन विभाग के संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और शिशु आहार आदि का भी विक्रय किया जाएगा।
- इन मेडिकल स्टोर्स से मिलने वाली जेनेरिक दवाइयाँ 20 ब्रांडेड कंपनी की होंगी, जो सस्ती होने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण भी होंगी।

नोट :

'इंडिया ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड'

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किये जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिये इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा 'इंडिया ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड' से नवाज़ा गया। छत्तीसगढ़ को यह अवॉर्ड बायोफ्यूल के आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन प्रोजेक्ट कैटेगरी में प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीबीडीए) रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिये अपरंपरागत ऊर्जा के नवीन विकल्पों को प्रोत्साहित कर रही है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा राज्य में बायोफ्यूल के क्षेत्र में अधिशेष अनाज से एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना, बायो-जेट एवीएशन फ्यूल के निर्माण में सहयोग और जैव ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान जैसे उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं।
- इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, 2020; भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सरदार शरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी एवं एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के सपोर्टिंग पार्टनरशिप में तथा केयर रेटिंग के नॉलेज पार्टनरशिप से अपारंपरिक ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोफ्यूल आदि में अवॉर्ड प्रदान किया गया।
- समग्र भारत से प्राप्त नॉमिनेशन में से भारत सरकार के वैज्ञानिक संगठन सीएसआईआर के साइंटिस्ट एवं शिक्षण प्रतिष्ठान आईआईटी के प्रतिनिधि वाले विशिष्ट ज्यूरी ने प्रत्येक कैटेगरी में अवॉर्ड हेतु चयन किया था।

'हैंडबुक ऑफ ओस्टियोपोरोसिस ए प्रीवेंटेबल डिजीज'

चर्चा में क्यों ?

- 22 अक्तूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में 'हैंडबुक ऑफ ओस्टियोपोरोसिस ए प्रीवेंटेबल डिजीज' नामक पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तक के लेखक शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्वशासी पीजी कॉलेज कालीबाड़ी रायपुर की डीन एवं प्रोफेसर डॉ. नंदा गुरवारा और पीजी नर्सिंग कॉलेज भिलाई के प्रोफेसर डॉ. डेजी अब्राहम हैं।
- इस पुस्तक में ओस्टियोपोरोसिस के कारण, लक्षण तथा उपचारात्मक परीक्षण और बचाव के उपाय व सही खान-पान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जो ओस्टियोपोरोसिस बीमारी के प्रति जनजागरूकता लाने सहित बचाव में काफी सहायक होगी।
- ज्ञातव्य है कि ओस्टियोपोरोसिस एक आम बीमारी है, जो भारत में 3 महिलाओं में से एक महिला और 8 पुरुषों में से एक पुरुष को प्रभावित करती है। यह हड्डियों को कमज़ोर तथा भंगुरमय कर देती है, जिससे कि व्यक्ति के थोड़े से टेंशन में होने पर, गिरने पर, खाँसने पर अथवा उम्र-दराज लोगों को फ्रैक्चर की समस्या आती है। यह फ्रैक्चर कमर, कलाई अथवा रीढ़ की हड्डी में होता है।

'ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप'

चर्चा में क्यों ?

- 24 अक्तूबर, 2021 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के तत्वावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राज्य के सभी सिविल ज़िलों में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ज़िला प्रशासन के समन्वय से ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने राज्य के सभी 23 सिविल ज़िलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप' का शुभारंभ किया।
- इस मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत किया जा रहा है।
- शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कर सभी वर्ग के लोगों तक न्याय पहुँचाने के साथ ही कानूनी सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना है।
- इस आयोजन में शामिल लोगों को विधिक सेवा की जानकारी एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहीमूलक सामग्री तथा आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया गया।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान 2 अक्तूबर, 2021 से मनाया जा रहा है, जो 14 नवंबर, 2021 तक चलेगा। इसमें आमजन को विधिक सेवा की जानकारी देने के प्रयोजन से प्रत्येक दिन ज़िला एवं तालुका स्तर पर विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रम, शिविर आदि आयोजित किये जा रहे हैं।

'वर्टेब्रोप्लास्टी' सर्जरी

चर्चा में क्यों ?

- 26 अक्टूबर, 2021 को रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में कशेरुक फ्रैक्चर के लिये पहली सफल 'वर्टिब्रोप्लास्टी' सर्जरी की गई।

प्रमुख बिंदु

- संस्थान के एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉ. विवेक पात्रे ने बताया कि तिल्दा-नेवरा (रायपुर) की 70 वर्षीय शकीला पाल की रीढ़ की हड्डी में हुए फ्रैक्चर के लिये एक न्यूनतम इनवेसिव वर्टेब्रोप्लास्टी सर्जरी की गई, जिसके लिये एक इमेज गाइडेड वर्टेब्रोप्लास्टी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया।
- इस उपचार के लिये मरीज़ से कोई ऑपरेशन शुल्क नहीं लिया गया था, क्योंकि रोगी को डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कवर किया गया था, जबकि अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर ऑपरेशन की न्यूनतम लागत 2 से 3 लाख रुपए तक आती है।
- इमेज गाइडेड वर्टेब्रोप्लास्टी प्रक्रिया में फ्रैक्चर साइट पर एक खोखली सुई के माध्यम से हड्डी में एक विशेष हड्डी सीमेंट इंजेक्ट किया जाता है। सीमेंट उस जगह पर जम जाता है, जिससे टूटी हड्डियों को सहारा मिलता है।

'भूलन द मेज' को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने छत्तीसगढ़ की फिल्म 'भूलन द मेज' को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- इस फिल्म को छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर मनोज वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाया है। इसमें एक्टर ओंकार दास मानिकपुरी ने काम किया है। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग का म्यूज़िक कैलाश खेर ने दिया है।
- यह फिल्म 'भूलन कांदा' उपन्यास पर आधारित है, जिसके लेखक संजीव बख्शी हैं।

नोट :

- 'भूलन कांदा' छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाया जाने वाला एक पौधा है, जिस पर पैर पड़ने से इंसान सब कुछ भूलने लगता है। रास्ता भूल जाता है, वह भटकने लगता है, इस दौरान कोई दूसरा इंसान जब आकर उस इंसान को छूता है, तब जाकर फिर से वह होश में आता है।
- फिल्म के ज़रिये आज के सामाजिक, इंसानी, सरकारी व्यवस्था में आए भटकाव को दिखाया गया है। इस फिल्म की शूटिंग गरियाबंद के भुजिया गाँव में हुई थी।
- उल्लेखनीय है कि 22 मार्च, 2021 को ही तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें छत्तीसगढ़ी बोली की फिल्म 'भूलन द मेज' को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिये नामित किया गया था।
- भूलन द मेज को इससे पहले कोलकाता, दिल्ली, ओरछा, आजमगढ़, रायपुर, रायगढ़ एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इटली एवं कैलिफोर्निया में भी पुरस्कार मिल चुका है।
- 'भूलन द मेज' के नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म का रिकॉर्ड भी बन गया है। नई फिल्म नीति के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की फिल्म को एक करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ शौर्य पदक

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में पुलिस मुख्यालय रायपुर ने बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को 'छत्तीसगढ़ शौर्य पदक' से सम्मानित करने के संबंध में आदेश जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- नक्सल मोर्चे पर कामयाबी दिलाने वाले इन जांबाज जवानों को एक नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा।
- सम्मानित होने वाले ये जवान पिछले कई वर्षों से नक्सलियों का सामना कर रहे हैं, नक्सल ऑपरेशन में कई बड़ी सफलताएँ दिलाई हैं तथा कई बड़े एनकाउंटर में शामिल होकर कई नक्सलियों को ढेर किया है।
- इन जवानों में 2 दंतेवाड़ा में तथा 5 नारायणपुर ज़िले में पदस्थ हैं। इनमें एक सहायक उप-निरीक्षक, चार प्रधान आरक्षक और दो आरक्षक शामिल हैं।
- सम्मानित होने वाले जवान हैं- सोमारू कड़ती (एएसआई, डीआरजी दंतेवाड़ा), केशर लाल सरोज (प्रधान आरक्षक, डीआरजी दंतेवाड़ा), बैसाखू राम सोम (प्रधान आरक्षक, नारायणपुर), पुनऊ राम दुग्गा (प्रधान आरक्षक, नारायणपुर), सकेंद्र कुमार नेताम (प्रधान आरक्षक, नारायणपुर), विवेक सिंह (आरक्षक, नारायणपुर) तथा रमेश कुमार अंधारे (आरक्षक, नारायणपुर)।
- इससे पहले भी दंतेवाड़ा की डीआरजी टीम के जवानों को पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें सबसे पहला नाम संजय पोटाम का आता है, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ 'शौर्य पदक' प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस

(1 नवंबर) को ड्यूटी के दौरान वीरतापूर्ण प्रदर्शन करने वाले राज्य पुलिस के जवानों को प्रदान किया जाता है। शौर्य पदक को मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है।

- यह शौर्य पदक कांसे का बना होता है, जिसके आगे के भाग में राज्य का प्रतीक चिह्न तथा पीछे के भाग में राजकीय वृक्ष 'साल' का चित्र अंकित होता है।

नोट :

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 28 अक्तूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में 'राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव' एवं 'राज्योत्सव, 2021' का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सेल्फी ज़ोन में पहुँचकर सेल्फी ली। समारोह स्थल पर आदिवासी संस्कृतियों तथा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश की झलकियों को समेटे आकर्षक सेल्फी ज़ोन भी बनाए गए हैं।
- कार्यक्रम में राज्यसभा के पूर्व सांसद बी.के. हरिप्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, युगांडा एवं फिलिस्तीन के काउंसलर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौज़ूद थे।
- राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न राज्यों एवं देशों से आए नर्तक दलों ने पारंपरिक वेशभूषा व वाद्य यंत्रों के साथ आकर्षक मार्चपास्ट किया।
- इस मौके पर मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से आए लोक नर्तक दल, उज्बेकिस्तान, स्वाजीलैंड के नर्तक दलों ने शानदार प्रस्तुति दी। हिमाचल प्रदेश के लोक नर्तक दल के कलाकारों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को हिमाचली टोपी और शॉल भेंटकर सम्मानित किया।
- रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में 28 अक्तूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस 'राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव' और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में देश के 27 राज्यों एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 7 देशों- एस्वातीनी, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, माली और फिलिस्तीन से आए लगभग 1500 कलाकार भाग ले रहे हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 42 जनजातियाँ और 5 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ निवास करती हैं। इनकी जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का एक-तिहाई है। सभी जनजातियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। उनकी बोली, उत्सव, नृत्य, देवी-देवता भी अलग-अलग हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का द्वितीय आयोजन है। इस महोत्सव का आयोजन पहली बार वर्ष 2019 में हुआ था, जिसका शुभारंभ कॉन्ग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किया था।

11वाँ मेडिकल कॉलेज

चर्चा में क्यों ?

- 28 अक्तूबर, 2021 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता की सूची जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार एनएमसी ने कांकेर मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 100 सीटों के लिये सशर्त मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तीन नए मेडिकल कॉलेज- कांकेर, कोरबा और महासमुंद में से केवल कांकेर मेडिकल कॉलेज को ही एनएमसी ने मान्यता दी है, जबकि कोरबा और महासमुंद का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। कोरबा और महासमुंद मेडिकल कॉलेजों को अगले सत्र में दोबारा आवेदन करना पड़ेगा।
- एनएमसी से मंज़ूरी मिलने के बाद अब कांकेर मेडिकल कॉलेज राज्य का 11वाँ मेडिकल कॉलेज व 8वाँ शासकीय मेडिकल कॉलेज होगा।
- इस मंज़ूरी के साथ ही राज्य में एमबीबीएस की कुल 1470 सीटें हो गई हैं।

नोट :

सिल्क मार्क

चर्चा में क्यों ?

- 29 अक्तूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने राजधानी रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास 'सतनाम सदन' में 'सिल्क मार्क' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने कहा कि अब राज्य में तैयार होने वाले शुद्ध देसी कोसा और रेशम वस्त्रों में सिल्क मार्क प्रमाणीकरण यूनिकोड लगाए जाएंगे। यूनिकोड लग जाने से इस बात की पुष्टि होगी कि तैयार किये गए रेशमी वस्त्र शुद्ध प्राकृतिक रेशमी धागों से ही निर्मित हैं और इन्हें बेहतर प्रतिसाद भी मिलेगा।
- प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी ने बताया कि राज्य सरकार की अभिनव पहल शुद्ध देसी रेशमी वस्त्रों को उचित बाज़ार और पहचान दिलाने में सहायक होगी।
- उन्होंने बताया कि इन शुद्ध देसी कोसा वस्त्रों के विक्रय से महिला स्व-सहायता समूह की आय में वृद्धि होगी, साथ-ही-साथ सिल्क मार्क प्रमाणीकरण से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्त्रों के विक्रय में सहायता भी मिलेगी।
- शुद्ध देसी कोसा वस्त्रों के उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम देश-विदेश में भी व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार में सहायक होगा। सिल्क मार्क लगे रेशम के वस्त्रों की बिक्री राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में लगे शिल्पग्राम के स्टॉल तथा शबरी एंपोरियम के स्टॉल में की जा रही है।

दृष्टि The Vision

नोट :